ब्याज दरें क्यों नहीं कम हो रही हैं

लेखक - उदित मिश्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

21 अक्टूबर, 2019

"फरवरी से आरबीआई ने अपनी ब्याज दर में 135 आधार अंकों की कटौती की है। फिर भी, नए ऋणों के लिए बैंक ऋण दरें बहुत कम नहीं हुई हैं, जबकि कई मौजूदा ऋणों पर ब्याज दर वास्तव में बढ़ गई है। इसका क्या मतलब है हम इस आलेख के जरिय समझेंगे।"

फरवरी से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर में आक्रामक कटौतियाँ की है। वह ब्याज दर है जो आरबीआई बैंकों पर लगाता है जब वह उन्हें पैसा उधार देता है। रेपो दर में कटौती करके, RBI शेष बैंकिंग प्रणाली को संकेत भेजता रहा है कि सिस्टम में उधार की दरें - ब्याज दरें जो बैंक आपसे और मुझसे ऋण लेते समय आपसे वसूलते हैं - नीचे आनी चाहिए। रेपो रेट में कटौती की इस प्रक्रिया को बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरों में कटौती के लिए 'मौद्रिक नीति संचरण' कहा जाता है।

परेशानी यह है कि भारत में यह प्रक्रिया कुछ हद तक अक्षम है। उदाहरण के लिए, फरवरी और अगस्त के बीच, RBI रेपो दर में 6.5% से 5.4% तक 110 आधार अंकों (जहाँ 100 आधार अंक एक प्रतिशत बिंदु बनाते हैं) की कटौती की। लेकिन, इस अवधि के दौरान बैंकों द्वारा नए सिरे से लिए गए ब्याज दर में केवल 29 आधार अंकों की गिरावट आई है - यह उस राशि का सिर्फ 27% है जिसके द्वारा रेपो दर में कमी आई है।

सुस्त संचरण से निराश, आरबीआई ने अक्टूबर में रेपो दर में एक बार फिर से 25 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया और बैंकों से अपनी उधार दरों को रेपो दर से जोड़ने का आग्रह किया। फिर भी, अधिकांश भाग के लिए, बैंकिंग प्रणाली ने इस संकेत को नज़रअंदाज़ कर दिया और इसलिए केवल कुछ बैंकों ने नए ऋणों पर ऋण दरों में 10 आधार अंकों की कमी की है। संक्षेप में, आरबीआई ने फरवरी के बाद से नौ महीनों में अपनी ऋण दर में 135 आधार अंकों (या 1.35 प्रतिशत अंक) की कटौती की है। इस दिवाली पर आम उपभोक्ता को लगने वाली ब्याज दरों में बैंको ने केवल 40 आधार अंक की कमी की है।

वास्तव में, भले ही यह प्रति-सहज है, मौजूदा ऋणों पर ब्याज दरें (नए ऋण नहीं) वास्तव में 7 आधार अंकों तक बढ़ गई हैं।

RBI क्यों चाहता है कम ब्याज दर?

फरवरी के बाद से, भारत की आर्थिक वृद्धि की गति में तेजी से गिरावट आई है। जीडीपी विकास दर का अनुमान फरवरी में लगभग 7.2% -7.5% से घटकर 5.8% -6.0% गई है। अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख समस्याएँ हैं और कम ब्याज दर से दोनों को हल करने में मदद् मिलने की उम्मीद है।

मुख्य मुद्दा यह है कि लोग उच्च पर्याप्त दर पर उपभोग नहीं कर रहे हैं। कागज पर, तर्क यह है कि यदि बैंक अपनी उधार दरों को कम करते हैं, तो उन्हें अपनी जमा दरों (ब्याज दर बैंक तब भुगतान करते हैं जब हम अपना पैसा उनके साथ बचत बैंक जमा या सावधि जमा करते हैं) को कम करना होगा। यह बदले में, लोगों को कम बचाने और अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में दूसरी समस्या यह है कि व्यावसायियों द्वारा मौजूदा या नई सुविधाओं में निवेश नहीं किया जा रहा है। इसका

एक कारण यह है कि लोगों द्वारा कम खरीददारी करने के कारण उनकी वस्तुएँ बिक नहीं रही हैं। लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि ऋण पर ब्याज दर काफी अधिक है। यदि बैंक ऋण पर ब्याज दरों को कम करते हैं, तो अधिक व्यवसायों को निवेश के लिए नए ऋण लेने के लिए उत्साहित होने की संभावना है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि सरकार ने हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स दरों में इस उम्मीद में कटौती की है कि यह कॉर्पोरेट क्षेत्र की लाभप्रदत्ता को बढ़ावा देगा और इससे और अधिक निवेश करने की सोच बढ़ेगी।

इसलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, रेपो दरों में कटौती का आरबीआई का निर्णय एक उचित कदम था, खासकर जब से समग्र खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के साथ अच्छी तरह से समायोजित है।

तो, ब्याज दरों में कमी क्यों नहीं आ रही है?

ऐसा इसलिए क्योंकि रेपो दर का बैंक की कुल लागतों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और सिर्फ इसलिए कि रेपो में कटौती की गई है उधार दरों को कम करने का निर्णय बैंकों के लिए उचित नहीं होगा।

किसी भी बैंक के व्यवहार्य होने के लिए, उधारकर्ताओं से उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर और ब्याज दरों के बीच एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए। ब्याज दरों के इन दो सेटों के बीच का अंतर न केवल सकारात्मक होना चाहिए, बल्कि बैंकों के लिए मुनाफा भी काफी बड़ा होना चाहिए।

जमा को आकर्षित करने के लिए, बैंक उच्च जमा दर का भुगतान करते हैं। इस तरह के डिपॉजिट सभी बैंकों के फंड का लगभग 80% हिस्सा बनाते हैं, जिससे वे फिर उधारकर्ताओं को उधार देते हैं। रेपो दर के तहत बैंक एक ऋण अंश का उधार लेते हैं। इसलिए रेपो दर को तेजी से कम करने से धन की कुल लागत में बदलाव नहीं होगा। इसलिए, जब तक बैंक अपनी जमा दरों को कम नहीं करते, वे अपनी उधार दरों को कम नहीं कर पाएंगे।

बैंक अपनी जमा दरों को कम क्यों नहीं कर रहे हैं?

ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि बैंक अपनी जमा दरों को कम करते हैं, तो जमाकर्ता एक प्रतिद्वंद्वी बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे अर्थात जो बैंक बेहतर ब्याज दर देगा या सार्वजनिक बचत कोष, सुकन्या समृद्धि योजना आदि जैसे छोटे बचत साधनों में अपनी बचत को अधिक से अधिक जमा करेंगे जिससे उन्हें अधिक से अधिक ब्याज दर प्राप्त हो।

यहाँ तक कि अगर बैंक अपनी जमा दरों को कम करने का सोचते भी हैं, तो भी वे उन्हें तुरंत कम नहीं कर सकते। मिरेन लोढ़ा, निदेशक, क्रिसिल रिसर्च, ने कहा कि कुल जमा का 65% 'सावधि जमा' (एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित) है और ताजा दरों पर दोबारा प्राप्त करने के लिए औसतन दो साल तक का समय लगता है। 'इसलिए, बैंक आम तौर पर अग्रिमों पर ब्याज दरों को कम करने पर धीमी गति से चलते हैं क्योंकि जमा पुनः प्राप्त होने में अधिक समय लगता है।

लेकिन मौजूदा ऋणों पर ब्याज दरें क्यों बढ़ रही हैं?

यदि बैंक नए ऋणों पर लगने वाले ब्याज दर को कम करने की सोचते हैं, तो इन्हें पुराने ऋणों पर ब्याज दरों को बढ़ाने पर भी सोचना होगा। इसका बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य से भी लेना-देना है। कमजोर बैंकों को पिछले घाटे के लिए दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा।

ऋण दर को रेपो दर से जोड़ने से कितनी सफलता मिली?

क्योंकि यह एक व्यवहार्य समाधान नहीं है। बैंक अपने उधार को रेपो दर से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रेपो से उनकी लागत का निर्धारण नहीं होता है।

एक रेपो-लिंक्ड प्रणाली के काम करने के लिए, पूरे बैंकिंग सिस्टम को उस पर स्थानांतरित करना होगा, दूसरे शब्दों में कहे तो बैंकों की उधार दरों के साथ, उनकी जमा दरों को भी रेपो के साथ ऊपर और नीचे जाना होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई नियम लागू होता है, तो जमाकर्ताओं को अपने बचत खाते पर 1.10 प्रतिशत अंक कम ब्याज दर प्राप्त होगी।

क्या कमजोर संचरण की यह समस्या नई है?

नहीं ऐसा नहीं है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रक्षित ने कहा कि अतीत में किसी भी समय मौद्रिक संचरण 50% से बेहतर नहीं रहा है (यानी, आरबीआई द्वारा केवल आधे दर में कटौती बैंकिंग प्रणाली द्वारा पारित की गई थी)। कमजोर संचरण का कारण भी, काफी हद तक एक ही रहा है।

विकसित देशों में ऐसा क्यों नहीं होता है?

ऐसा इसलिए क्योंकि वित्तीय प्रणाली अधिक विकसित और विविध है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ की बैंकिंग प्रणाली को अर्थव्यवस्था में सभी को ऋण प्रदान करने का बोझ नहीं उठाना पड़ता है – एक छोटे व्यक्तिगत ऋण से लेकर एक बड़े व्यवसाय ऋण तक या एक फ्रिज खरीदने से लेकर एक कारखाना स्थापित करने तक। बड़े ऋणों के लिए अधिकांश माँगों को कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की ओर निर्देशित किया जाता है – जिसमें एक कंपनी बॉन्ड (या IOUs) जारी करती है और बाजार जो भी ब्याज दर की माँग करता है उसका भुगतान कर के वह जनता से पैसा उधार लेता है।

इसके अलावा, जमाकर्ताओं को अपने ऋण पर परिवर्तनीय ब्याज दर की उम्मीद करते हुए अपनी बचत पर एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त करने की आदत नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के वर्तमान निम्न स्तर पर, बचतकर्ता भारत में कहीं अधिक जोखिम में हैं और बैंक जमाओं के अलावा उच्च-जोखिम वाले साधनों में निवेश करने को तैयार नहीं हैं।

अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा समग्र रूप से उधार लेना – जो कि सरकारी और सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ हैं – इतनी अधिक नहीं हैं कि को अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को बढ़ा सकें।

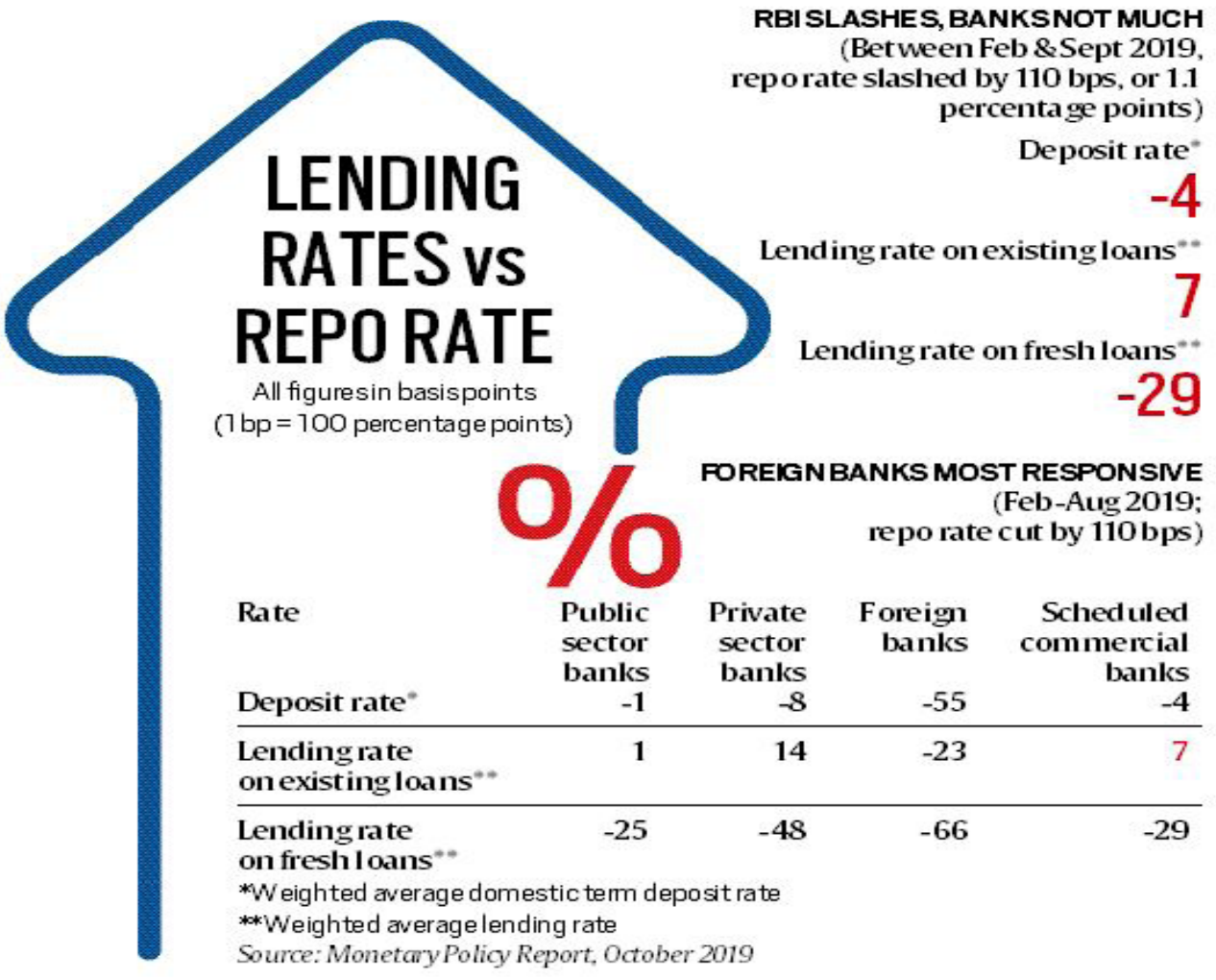

Rate	Public sector banks	Private sector banks	Foreign banks	Scheduled commercial banks
Deposit rate*	-1	-8	-55	-4
Lending rate on existing loans**	1	14	-23	7
Lending rate on fresh loans**	-25	-48	-66	-29

*Weighted average domestic term deposit rate
**Weighted average lending rate
Source: Monetary Policy Report, October 2019

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. आर.बी.आई. की रेपो-लिंक्ड प्रणाली के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

   1. रेपो लिंक्ड प्रणाली के काम करने के लिए पूरे बैंकिंग सिस्टम को उस पर स्थानांतरित करना होगा।
   2. इसके तहत बैंकों को अपनी उधार दरों को रेपो दर से जोड़ना होगा।
   3. अगर यह प्रणाली लागू होती है तो जमाकर्त्ताओं को अपने बचत खाते पर 2.1% अंक कम ब्याज दर प्राप्त होगी।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) 1 और 3
   (c) 2, और 3
   (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context to repo-linked system of RBI.**

   1. For the repo linked system to work, the entire banking system has to be transferred to it.
   2. Under this, banks have to link their lending rates with the repo rate.
   3. If this system comes in to force then depositors will get 2.1% less interest rate on their savings account.

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 2
   (b) 1 and 3
   (c) 2 and 3
   (d) 1, 2, and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगातार मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दरें कम की गई हैं, किन्तु इसका वास्तविक लाभ जनता तक नही पहुंच पा रहा है। इसका क्या कारण है? वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Interest rates have been reduced by the Reserve Bank of India through continuous monetary policy, but its real benefit are not reaching the public. What is the reason for this? What steps need to be taken by commercial banks? Discuss (250 words)

नोट : 19 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।